भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 285

दिनांक **19** जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

उन्नत पशुधन सशक्त किसान सम्मेलन

285. डॉ.डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उन्नत पशुधन सशक्त किसान सम्मेलन का आयोजन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी रही है;
(ग) सम्मेलन के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और उसके परिणाम का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने किसानों के घर तक गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का विचार पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्रों को अधिक महत्व देने का है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(च) पशु स्वास्थ्य और ऋण सेवाओं तक किसानों की पहुंच को बढ़ाकर पशुधन क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग) आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर डेयरी, कुक्कुट और अन्य पशुधन किसानों, नवाचारी उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 01 जून, 2022 को उन्नत पशुधन उन्नत किसान सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में लगभग 1200 किसानों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर और देशभर से 50,000 किसानों ने सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये थे:-

(i) 75 देसी पशुधन नस्लों की डिजिटल प्रदर्शनी

(ii) पशुधन क्षेत्र में 75 सफल उद्यमियों पर डिजिटल प्रदर्शनी

(iii) 75 पशुधन नस्लों और 75 उद्यमियों पर दो डिजिटल कॉफी टेबिल पुस्तकों का विमोचन।

(iv) एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन (ए-हेल्प) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।

(v) पशुपालन क्षेत्र में पदमश्री पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन

(vi) पशुपालन स्टार्ट-अप ग्रांड चैलेंज 2.0 के विजेताओं की घोषणा।

(vii) 1) उत्पादकता बढ़ाना और पशु स्वास्थ्य को सुधारना, 2) मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क तथा 3) नवाचार और प्रौद्योगिकी पर तीन तकनीकी विषय-वस्तु संबंधित सत्र

(घ) किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2021-22 से किसानों के द्वारा पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना" के तहत "पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट (ईएसवीएचडी-एमवीयू)" लागू किया है। यह योजना प्रति एक लाख पशुधन आबादी के लिए मोबाइल पशुचिकित्सा यूनिट (एमवीयू) की खरीद पर आने वाले गैर-आवर्ती व्यय के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों द्वारा निदान और उपचार सेवाओं को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए, योजना पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों के लिए 90%, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य सभी राज्यों के लिए 60% की केंद्रीय हिस्सेदारी प्रदान करती है। वर्ष 2021-22 के दौरान 4332 मोबाइल पशुचिकित्सा यूनिटों (एमवीयू) की खरीद के लिए 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 681.57 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ड.) हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2021-22 से प्रारंभ होकर अगले पांच वर्षों के लिए देशभर में पशुपालन और डेयरी के केंद्रित विकास के संबंध में मौजूदा योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुनर्संरेखित किया है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देशभर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रहा है:

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
iii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि
iv. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता
v. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
vi. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
vii. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

viii. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

ix. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

x. मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि

(च) पशुधन क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए देश में खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रूसेलोसिस रोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) लागू किया जा रहा है जिसका उद्देश्य एफएमडी के लिए गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का 100% टीकाकरण और ब्रूसेलोसिस के लिए टीकाकरण करने के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना के तहत, "पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)" नामक घटक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के टीकाकरण, रोग निदान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्रीय सहायता (पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों के लिए 90% संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य सभी राज्यों के लिए 60%) प्रदान करता है। योजना में पेस्टे-डेस-पेटिट्स रूमीनेंट्स- उन्मूलन कार्यक्रम (पीपीआर-ईपी) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम (सीएसएफ-सीपी) भी शामिल है जो देश में 100% पात्र भेड़ और बकरी तथा सुअर की आबादी को कवर करते हुए भेड़ और बकरियों के पेस्ट-डेस-पेटिट्स रूमीनेंट्स (पीपीआर) रोग के अन्मूलन और टीकाकरण द्वारा सुअरों के सीएसएफ रोग के नियंत्रण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र तक ऋण सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, विभाग, डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ) जैसी क्रेडिट संबद्ध अवसंरचना विकास योजनाएं और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के तहत नस्ल वृद्धि फार्म, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भेड़, बकरी, सुअर प्रजनन फार्म और ग्रामीण कुक्कुट पालन में नस्ल विकास जैसी क्रेडिट संबद्ध उद्यमिता योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। देश में पशुपालन और डेयरी किसानों को नये केसीसी प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सहयोग से विशेष अभियान चलाए गए थे। विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सहयोग से वर्तमान में दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 31.07.2022 तक एक राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान चला रहा है। बढ़ा हुआ ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान पशुपालन और डेयरी के लिए जमीनी स्तर के ऋण लक्ष्य के रूप में 1,04,580 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

****